



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] मई दिल्ली, सोमवार, मई 10, 1982/वैशाख 20, 1904
No. 89] NEW DELHI, MONDAY, MAY 10, 1982/VAISAKHA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात वगैरह नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 23आई०टी०सी० (पीएन)/82

नई दिल्ली, 10 मई, 1982

विषय : 1981-82 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई येन 1.134 बिलियन (ऋण सहायता) की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

मिस्त्रिल सं० आईपीसी/23 (31)/82—1981-82 के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई येन 1.134 बिलियन (ऋण सहायता) की जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लागू होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अभिमुखित की जाती हैं।

मणि नागयण्स्वामी, मुख्य नियंत्रक
आयात एवं निर्यात

संबंधित सूचना सं० 23आई०टी०सी० (पीएन)/82 दिनांक 10-5-1982 का परिशिष्ट 1

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1981-82 के लिए 1.134 बिलियन (येन 1,134,696,000) (ऋण सहायता) की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के संबंध में लाइसेंस शर्तें।

खंड 1—सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 1.134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता भारत के अलावा ओ०ई०सी० वी० और विकास-शील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्ति की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रारंभिक सेवाएं अत्यांत और अनुबंध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती हैं। ये देश इस अनुदान के अन्तर्गत पात्र क्षेत्र देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र सदे आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबंध 2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक प्रीपैक 1981-82 के लिए 1.134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत 'एम/जे-एन' होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अधिपत्र में भी दृष्टांत जाएंगे।

1(3) बैंक खाते, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अनिवार्य विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषित की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारत में अधिकतम के कमिशन के प्रति कोई भी भुगतान अधिकता की भारतीय रुपय में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस सत्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारंभिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को सबड लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क

करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबंध 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर किए जाने चाहिए और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर) भ्रष्ट सचिव (टी.ए.) आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। 'पक्के आदेशों' का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा किए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकारियों के आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकारियों द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की हम शर्त का नव तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण वस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यदा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर बैंक कार्यों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करने हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आदेशों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इन लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों के अतिरिक्त के लिए मांगी जाती है, तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे।

पोत लघान के लिए आखिरी तिथि निर्धारित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1983 के बाद की न हो।

अध्या 2—संभरण ठेके का समतोल करने समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:—

2(1)(क) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन या यू० एम० शालर या पीण्ड स्टलिंग में एक येन, एक सेट या एक पेनी से कम की मात्रा के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसमें भारतीय अधिकारों का कमोशन यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए जहाँ पर्यन्त निशुल्क लागत बीमा और भाड़ा खनराशि अलग अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का अर्ध वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का अर्ध वास्तविक अर्ध के अनुरिक्त देय खनराशि होगी।

(ख) संविदा में तुरन्त आधार पर अर्धान् बैंक आक इण्डिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलक्षण वस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए।

2(2) आयात लाइसेंस के बिना केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले जना चाहिए।

(23) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र लोग देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र लोग देशों में पंजीकृत और समाविष्ट व्यापिक व्यक्ति होगा।

अध्या 3 संभरण ठेकों में भिन्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए:—

3(1) 1981-82 के लिए 1,134 बिलियन के अनुमान समुपता से सम्बद्ध इस संविदा की व्यवस्था 6 फरवरी, 1982 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उन भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी) के माध्यम से लिया जाएगा जो 1981-82 के लिए जापानी अनुमान समुपता के अन्तर्गत बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो के नाम में गढ़ायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक लिमिटेड, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली, 110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी और जापान सरकार द्वारा अंग्रेजित हो।

3(4) उस मामले में जिनमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय वृत्तावास टोकियो के परामर्श से पोतलक्षण की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए सम्बन्धित मात की सुपुर्दा के कार्यक्रम की भारतीय वृत्तावास, टोकियो को सूचना देगा और अंग्रेजित पोत परिचय के लिए कम से कम 6 सप्ताह से पहले ही भारतीय वृत्तावास टोकियो को अधिभूचित करवाएगा जिनमें उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिभूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक होकर देने हुए प्रत्येक पोतलक्षण के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय वृत्तावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

अध्या 4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन

4(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाने के, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों, द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र पार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए एक आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या उनकी सभी प्रकार में पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध 3 के प्रपत्र में 'ए/पी' जारी करने के आदेशों की 2 प्रतियां सहित संलग्न बैंक आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतिता अर्ध सचिव (टी-ए) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषयवस्तु या उसकी कीमत के आधारक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

4(2) यदि ठेके के वस्तावेज 'ए/पी' जारी करने के लिए आवेदनपत्र, और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, और भाग के राजवृत्तावास, टोकियो और भारत में जापान के राजवृत्तावास को भेजने व्यवस्था करेगा।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो के लिए अनुबंध 4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करेगा। ए/पी की प्रतियां भारत के राजवृत्तावास, टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पुष्टिकृत की जाएंगी।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक के भारत में बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देने हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4(5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित वास्तविक बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को वेब बैंक खाते, भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खंड 5—गणना जमा करने का उत्तरदायित्व

5(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज निरववाद रूप से बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक [जो अनुबन्ध 3 के (घो) में उल्लिखित हैं] की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई धन/यू० एस० डालर/पौण्ड स्टलिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है व्याज के खर्चे सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब खाताकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46 आई टी सी (पी एन) /76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103 आई टी सी (पी एन) /76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संघीयित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी/(पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों को येन यू० एस० डालर/पौण्ड धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं०-8 आई टी सी (पी एन) /76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिचरों, के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। आईसेंसधारी का भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकों से दस्तावेज लेने से पहले ही वेय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह 'के डिपोजिट एण्ड रजिस्ट्रार—843—मिखिल डिपोजिट—डिपोजिट फोर परवेजिस एटसेटरा एंडाउ परवेजिस ग्रान्ट ऐंड फ्राम गवर्नमेंट ऑफ जापान फार एण्ड 1981-82 (वेन 1,134 बिलियन ग्रान्ड ऐंड ऋण—सहायता।

5(2). उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार को पाब में 161

जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्राप्त) की सार्वजनिक सूचना सं० 184 आईटीसी (पी एन) /68, दिनांक 30-8-68 सं०-233-आईटीसी (पी एन) /68, दिनांक 24-10-68 सं०-132-आईटीसी (पी एन) /71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पी एन) /74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पी एन) /76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए जन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक की ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खातों के निमित्त योजना जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। बालान के विभिन्न कालनों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103 आईटीसी (पी एन) /76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132 आईटीसी (पी एन) /71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं०-74 आईटीसी (पी एन) /74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना बालान के कालन "घन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ध्येय" में निरववाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना बालान में निम्नलिखित ध्येय निरववाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :—

(क) जिस मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में धनवाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना जाएगा।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(व्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समस्त रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है।

उसके पश्चात् सी० ए० ए० एंड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देने हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करने हुए खजाना बालान बनाया जमा करने का साध्य देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एंड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी: भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो से आयाती की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरववाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० ए० विल मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली व सूचित कर दिया जाएगा।

5 (4) भारत में सम्बद्ध बैंक ऑफ इंडिया, को आईसेंस की मु विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन कर चाहिए और उपर्युक्त 'एस' प्रवर्ग भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया - योजना चाहिए।

खंड 6—विधिगत शर्तें

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की शर्तें

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को लदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पं

प्रदान होने जाको है उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी० ए० ए० पृष्ठ ९०
...क कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू० सी० प्रो० बैंक विविध, संसद मार्ग
...बिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2) संभरकों की विशेष शर्तें अधिसूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से
...को प्रमाण करावें जो संभरकों का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव
डाल सकती हैं।

6(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि
कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं
लेगी। बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूर्ण की
जाने वाली शर्त साफ-साफ 'भुगतान के निगम' के अधीन अनुबंध 1 में दर्शाई
जाती चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी
चाहिए।

6(4) अधिकृत अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले
या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1981-82 के लिए अनुदान सहायता
के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-
समय पर जारी किए निर्देशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त
पालन करना होगा।

6(5) प्रतिक्रमण या उल्लंघन :

उपयुक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उल्लंघन करने
पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की
जाएगी।

6(6) अनुबंध की सूची :

अनुबंध—1 पात्र क्षेत्र क्षेत्रों देशों की सूची

अनुबंध—2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबंध—3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन
करने का प्रपत्र।

अनुबंध 4—भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र

पात्र क्षेत्र देशों की सूची

(क) प्रो० इ० सी० डी० देश

आस्ट्रेलिया

बेल्जियम

कनाडा

डेनमार्क

फिनलैंड

फ्रांस

जर्मनी संघीय गणराज्य

यूमान

आइसलैंड

आयरलैंड

इटली

जापान

लक्जमबर्ग

द्वि नीदरलैंड

न्यूजीलैंड

नार्वे

पुर्तगाल

स्वीडन

स्वीडन

स्वीट्जरलैंड

तुर्की

द्वि युनाइटेड किंगडम

और युनाइटेड स्टेट्स

(ख) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(ख-1) नान-प्रो० पी० ई० सी० विकासशील देश

1. अफ्रीका, उत्तरी सहारा

मिश्र

मोराको

तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा

अंगोला

बोत्सवाना

बुरुंडी

केमरान

केप वर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र

काद

कमोरो द्वीप समूह

इथोपिया

जाम्बिया

कांगो, दमोह गणराज्य

इक्वेटोरियल गार्इना

घाना

गिनी

ग्राइबरी कोस्ट

कीनिया

लेसो थो

लाइबेरिया

मालीगासी गणतंत्र

मलावी

माली

मारिसेनिया

मारीशिस

मोजाम्बिक

नाइजीरिया

पुर्तगाल गिनी

रियूनियन

रोडेसिया

रवाण्डा

सेंट हेलेना और जेप (2)

साओटोम प्रिंसाइड

सेनेगाल

सेचिलीज

सियरा लिओन

सोमालिया

सूडान

स्वाजीलैंड

टंगो अफांस और इस्तास

टोंगो

युगांडा

तमजानिया गणतंत्र संघ

अपर बोस्टा

जाग्रहे गणतंत्र

जाम्बिया

3. अमेरिका-- उत्तरी और केन्द्रीय :

बेहमस

बारबाडोस

बेलाइज

बरगुडा

कोस्टोरिका

क्यूबा

डोमिनिकन गणतंत्र

एस साल्वडोर

गुवाटेमाला

ग्वाटेमाला

हेती ।

होन्डुरस

जैमेका

मार्टिनिक ब्यू

मेक्सिको

नीदरलैण्ड एंटाटिलीज

निकारागुआ

पनामा

सेंट पियरी और मिक्यूलीन

ट्रिनिडाड और टोबागो

वेस्ट इंडीज (शाखा) एन० आई० ई०

(क) संबन्धित राज्य (1)

(ख) प्राश्रित राज्य (2)

- (1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, परनेबी पी द्वीप समूह।
- (2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : असेंशन, ट्रिस्टन डा हन एक्सेम्बिलिस, मार्टिगेल गफ।
- (3) मेन समूह, अरूबा, बोनेर, क्याकाओ साहा, सेंट युस्टासिट, सेंट मारटिन (दक्षिण भाग)।

4. दक्षिणी अमेरिका :

अर्जेन्टीना

बोलिविया

ब्राजील

चिली

कोलंबिया

फाकलैंड द्वीपसमूह

फ्रांसिसी गिनी

गुयाना

पाराग्वे

पीरू

सुरिनाम

उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :

बैहरीन

इजरायल

जोर्डन

लेबनान

ओमान

सिलिआई अरब गणतंत्र

यूनाइटेड अरब एमिरात

यमन अरब गणतंत्र (3)

यमन जनवादी डी० आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया :

अफगानिस्तान

बांगलादेश

भूटान

बर्मा

मालदीव

नेपाल

पाकिस्तान

श्रीलंका

7. सुदूर पूर्व एशिया :

बुर्नेई

हॉंगकांग

ख्मेर गणतंत्र

कोरिया गणतंत्र

लाओस

मकाओ

मलेशिया

फिलिपाइन

सिंगापुर

ताइवान

थाइलैंड

तिमोर

वियतनाम गणतंत्र

वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया :

कोक द्वीप समूह

फिजी

गिल गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप

फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)

नोर्क

न्यूकोलेडोनिया

न्यूहेब्रिडिस

ट्रिनि

पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)

पापुआ न्यू गिनी

सोलामन द्वीप समूह (त्रि)

टोंगो

वालिस और फुतुना

पश्चिमी समाओ

9. यूरोप :

साइप्रस

जिब्राल्टर

ग्रीक

माल्टा

स्पेन

टुर्की

यूगोस्लाविया

- (1) मुख्य द्वीप एंडिगुआ, डोमिनिका, ग्रीनेडा, सेंट क्रिस्ट (सेंट क्रिस्टफो टोफो) नेविस, अंगुइला, सेंट लूसिया और सेंट विलेज।
- (2) मेन आई लैण्ड, मोन्टे से रेन, गमान, तुर्की और काइकेस और ब्रिटिश बरजिन द्वीपसमूह।
- (3) अजमन, दुबई, फुजाइरह, शाम अल खमाह शरजाह और उम अल कववन।
- (4) अदन और बिभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित।
- (5) सोसायटी आइ लैण्ड समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह, दुआमोट, जॉर्जिया द्वीप और मार्केस द्वीप समूह।
- (6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (ग्राम को छोड़कर)।

(ब-2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया
बोत्सवाना
लीबियाई अरब गणतंत्र
गबान
नाइजीरिया
दक्षिण अफ्रीका
बेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
भाबुवाबी
इंडोनेशिया।

अनुबंध-2

पक्ष पक्ष सूची

1. रोलज
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात
3. टर्कों और ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे
4. रसायन
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे संघटक और कच्चा माल
6. बिजली के हलों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे
7. मशीनरी, संघटक, संयोजन, फालतू पुर्जे और कच्चा माल
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और उपस्कर
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग परियोजना के लिए मशीनरी और उपस्कर
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मर्चें जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबंध-3

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र”

सं०

दिनांक

सेवा में,

सहायता सेवा तथा सेवा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यूसीपी बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल
पालियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

विषय :— 1981-82 के लिए 1.134 बिलियन जापानी अनुदान सहायता
येन के अधीन जापान से आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से जो कि
..... आयात के संबंध में है संबंध संभरक के नाम

में बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की सं०, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या निविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) निविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि।

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) संभरकों के साथ की गई निविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) संभरक का नाम और पता

(ट) वे भुगतान गतों और संभावित तिथि जिनको निविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) सुपुर्देगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करने समय लिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें। प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए।)

(ढ) पोतलवान अनुदेश (बाह्यनांतरण/पार्टे-शिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निविष्ट कीजिए।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(त) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत निविदा (निविदाओं) कर दी गई है। यदि हां, तो ऐसी निविदा की दिनांक और मूल्य।

महोदय

अनुबंध - 4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग,

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक ऑफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय : 1.134 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन
आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न ब्यौरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वोत्तरी भाग

में येन अनुराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठीकृत की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित खदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपकी दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित भरा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े में टोकियो भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए खदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र सं० दिनांक के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो, बैंक से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येम/यूएम डालर/पीड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों की चुकायी गई अनुराशि के बराबर रुपय की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की सिद्धित वर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेख में तुल्य रुपय जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से व्याज भी सरकारी लेख में जमा कराना होगा। व्याज दो दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेख में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह मुनि-निश्चय कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमाशुल्क निवानी के लिए आयातक दस्तावेजों का मूल मेट दिए जाने से पूर्व यह अनुराशि जमा की जाती है।

ये अनुराशियां या सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीम हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुबंधी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीम हजारी शाखा, दिल्ली-6 (अदेखित और आदाता) के नाम में और उसको

वेय दर्शनी हुंडी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 23-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-68, सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें अनुराशि जमा की जाएगी वह 'के डिपोजिट्स एंड एडवांसिस-843 निविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परसेसिस एटसेट्टा बाइ—परसेसिस ग्रांट ऐंड फायम दि गवर्नमेंट ऑफ जापान फार 1981-82 (येन 1.134 बिलियन ग्रांट ऐंड डेबट रिलीफ)';

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीम हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार तकद जमा किया जाता है उनमें चलान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देने हुए अप्रवेशन पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पत्र पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षानियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्णनी हुंडी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पत्र पर भेजी जाएगी। सभी मामलों में व्याज की चुकाई गई अनुराशि और जिस अवधि के लिए रुपय की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपय का पूरा व्यौर इस विभाग को भेजा जाएगा।

समुदाय संभरक के बैंक के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्च और बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो बैंक के अन्य खर्च इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवध मन्त्रिय (टीए) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 23-ITC(PN)/82

New Delhi, the 10th May, 1982

Subject :—Licensing condition in respect of public sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 Billion (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan.

File No. IPC/23(31)/82.—The terms and conditions governing the issuance of import licences in respect of public sector imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 Billion (Debt Relief) for 1981-82 extended by the Government of Japan as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 23-ITC(PN)/82 Dated the 10-5-1982

Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 Billion (Y 1,134,696,000) (Debt Relief) for 1981-82 Extended by the Government of Japan

Section I—General Conditions :

(i) The Japanese Grant Aid of Yen 1.134 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries except India. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured

under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 1.134 billion Japanese Grant Aid for 1981-82". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licensee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas supplied duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1983.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract :

II(i) (a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior appro-

val of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(iii) Eligibility of Supplier :

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III :

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 6th February, 1982 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.134 billion for 1981-82 "and will be subject to the approval of Government of India".

III(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1981-82.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India :

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licensee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Japan Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A, the Embassy of India, Tokyo and the Embassy of Japan in India.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US\$/Pound sterling Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculated at the rate of 9% per annum for the first thirty days and at 15% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 193-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US\$/£ Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licensee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1981-82 (Yen 1,134 billion Grant Aid—Debt-relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. 167 GI/82--2.

The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the foreign supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

VI(iv) Future Instructions :

The licensee shall promptly comply with directions, instructions, or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1981-82 from Japan.

VI(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act)

VI(vi) List of Annexures :

Annexure-I—List of eligible source countries

Annexure-II—List of eligible commodities

Annexure-III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE I

List of eligible source countries

A. OECD Countries :

Australia
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
The Federal Republic of Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Luxembourg
the Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
the United Kingdom and
the United States

B. Developing Countries and Territories :

(b1) Non-O.P.E.C. Developing countries

I. AFRICA, North of Sahara :

Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara :

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's
Republic of Dahomey (1)
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep (2)
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and
Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands : Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit, St. Martin (Southern Part).

III. AMERICA, North and Cent.

Bahamas
Barbadoses
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre and Miquelon
Trinidad and Tobago
West Indies (Br.) n.l.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South :

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East :

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South :

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East :

Borneo
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Vietnam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

- (1) Main islands : Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis, Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands : Montserrat, Guyana, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.

VIII. OCEANIA :

Cook Islands
 Fiji
 Gilbert and Ellice Is.
 French Polynesia (5)
 Nauru
 New Caledonia
 New Hebrides (Br. and Fr.)
 Niue
 Pacific Islands (U.S.) (6)
 Papua New Guinea
 Solomon Islands (Br.)
 Tonga
 Wallis and Futuna
 Western Samoa

IX. EUROPE :

Cyprus
 Gibraltar
 Greece
 Malta
 Spain
 Turkey
 Yugoslavia

(b2) Member or Associate Countries of OPEC :

Algeria
 Bolivia
 Libyan Arab Republic
 Gabon
 Nigeria
 Ecuador
 Venezuela
 Iran
 Iraq
 Kuwait
 Qatar
 Saudi Arabia
 Abu Dhabi
 Indonesia

ANNEXURE II

Eligible Commodity List

1. Rolls
 2. Steel including special steel and alloy steel
 3. Components, attachments and spares for manufacture of trucks and tractors.
 4. Chemicals
 5. Spares, components and raw materials for Japan aided Projects and Indo-Japanese Joint Venture.
 6. Components, attachments and spares for power tillers
 7. Machinery, components, attachments, spares and raw materials.
 8. Machinery and equipment for the National Small Industries Corporation of India.
 9. Machinery and equipment for the Oil and Natural Gas Commission Projects.
 10. Fertilizer and such other items as may be mutually agreed upon.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands; Caroline Islands Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

ANNEXURE III

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
 Ministry of Finance,
 Department of Economic Affairs,
 UCO Bank Building, 1st Floor,
 Parliament Street,
 New Delhi-110001.

Subject :—Import from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 1.134 billion for 1981-82.

Sir,

In connection with the import of _____ from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Supplier concerned :—

- (a) Name and Address of the Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal open International tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen) if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Suppliers.
- (j) Name and Address of the supplier.
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/ partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's Bank in India.
- (p) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and if so, the No., date and value of such contract.

ANNEXURE IV

No.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To

The Bank of India,
 Tokyo Branch,
 Tokyo (Japan)

Subject :—Import under Japanese Grant Aid for Yen 1.134 billion Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 13-3-1979 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s. _____ (as per details given in the Appendix)

2. Please advise the Suppliers of the fact of receipt of this authorisation to pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers' Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents etc. as indicated in the Appendix.

4. The banking charges including charges for handling documents payable to you by the importer will be settled by the Embassy of India, Tokyo Importers Bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendments to A/P may be issued in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. The A/P will remain valid upto _____

Yours faithfully,

Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____

2. Importer's Banker _____ they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen/US \$/£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notice as may be issued from time to time. Interest @ 9% per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is

made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 23-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN) 74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1981-82 (Yen 1.134 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)